



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2009 ई0 (कार्तिक 30, 1931 शक सम्वत्) [संख्या-47

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	467-483	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	331	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, मोटीफाईड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	—	1425
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	—

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## गृह अनुभाग-4

उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन को विनियमित करने  
सम्बन्धी नियमावली, 2009

05 नवम्बर, 2009 ई०

संख्या 823/XX(4)-01/उ०आ०/2009-1-(1) इस नियमावली का नाम "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों प्रदत्त पेंशन तथा अनुदान नियमावली, 2009" कहलायेगी।

(2) यह नियमावली प्रख्यापित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

## 2-परिभाषाएँ-

(1) इस नियमों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो-

(2) इस नियमावली के निमित्त "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी" का तात्पर्य ऐसे राज्य आन्दोलनकारियों से है जिन्होंने पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में भाग लिया हो और जो शासनादेश संख्या 1269/तीस-2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थे, लेकिन जो किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो पाये।

## स्पष्टीकरण-

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार दी जायेगी :-

1-राज्य आन्दोलन के दौरान ऐसे आन्दोलनकारी जो शासनादेश संख्या 1269/तीस-2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थे, लेकिन जो किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो पाये, पेंशन अनुमन्य हेतु पात्र होंगे।

2-पात्र उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को रु० 3000/- (रुपये तीन हजार) प्रतिमाह की दर से पेंशन उनके जीवन काल के लिये स्वीकृत की जायेगी।

3-ऐसे उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, को कार्य के मूल दावे प्रस्तुत करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उस पर संस्तुति/प्रतिहस्ताक्षर करने के बाद उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनकी पत्नी अथवा विधवा को दांत लगवाने, चश्मा बनवाने तथा श्रवण यंत्र क्रय करने के लिए अधिकतम रु० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का अनुदान जीवन में एक बार स्वीकृत किया जायेगा।

4-पेंशन हेतु धनराशि का भुगतान पेंशन हेतु बनाये गये कारपस फंड से वहन किया जायेगा।

5-"राज्य आन्दोलनकारी को दिये जाने वाली पेंशन" का तात्पर्य रुपये 3000 (रुपये तीन हजार मात्र प्रतिमाह) की ऐसी धनराशि से है जो किसी राज्य आन्दोलनकारी को इन नियमों के अधीन स्वीकृत किया जाय।

3-पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया तथा अधिकार-

(1) इन नियमों के अधीन कोई पेंशन या अनुदान जिलाधिकारी की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अनुदान राशि के आहरण एवं भुगतान हेतु महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और इसका भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सत्यापन द्वारा सीधे ही कर दिया जाएगा।

(3) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन की कोई धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाय तो भुगतान सामान्य विधि के अनुसार उत्तराधिकारी को कर दिया जाये। पेंशन पा रहे आन्दोलनकारी की मृत्यु के दिनांक को पेंशन समाप्त हो जायेगी।

राज्य आन्दोलनकारी पेंशन बन्द करना-

जो व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेंशन अथवा अनुदान प्राप्त कर रहे हों अथवा प्राप्त करने के लिये आनेदन-पत्र या कोई स्वयं प्रमाण-पत्र दिया हो, जो गलत पाया जाय तो स्वीकृत पेंशन अथवा अनुदान किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा पेंशन के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव।

## ऊर्जा अनुभाग-1

### अधिसूचना

28 अक्टूबर, 2009 ई०

संख्या 1659/1/2009-01/(2)-04/2006--'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्युत सुरक्षा लिपिक एवं लेखा वर्गीय सेवा में शर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड विद्युत सुरक्षा लिपिक एवं लेखा वर्गीय सेवा नियमावली, 2009

### भाग एक -सामान्य

#### 1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत सुरक्षा लिपिक एवं लेखा वर्गीय सेवा नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

#### 2-सेवा की प्राप्ति-

उत्तराखण्ड विद्युत सुरक्षा लिपिक एवं लेखा वर्गीय संवर्ग सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

#### 3-परिभाषाएं-

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ख) "विद्युत निरीक्षक" से विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ग) "विद्युत सुरक्षा विभाग" से विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार के संगठन अभिप्रेत है;
- (घ) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो "भारत का संविधान" के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
- (ङ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
- (च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;
- (ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्य पालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; और
- (ज) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

### भाग दो-संवर्ग

#### 4-सेवा का संवर्ग-

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी :-

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	वैयक्तिक सहायक-सह-कन्सोल ऑपरेटर	1	—	1
2.	लेखाकार-सह-कन्सोल ऑपरेटर	1	—	1
3.	प्रवर सहायक	1	—	1
4.	आशुलिपिक-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	3	—	3
5.	कनिष्ठ सहायक	6	—	6

परन्तु यह कि—(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें व उचित समझे।

### भाग तीन-भर्ती

#### 5-भर्ती का स्रोत-

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात् :-

#### पद का नाम

#### भर्ती की रीति

(एक) कनिष्ठ सहायक-नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से।

(दो) आशुलिपिक-सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से।

(तीन) प्रवर सहायक-

स्थायी कनिष्ठ सहायकों में से, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति द्वारा।

(चार) लेखाकार-सह-कन्सोल ऑपरेटर-

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से।

(पांच) वैयक्तिक सहायक-सह-कन्सोल ऑपरेटर-

स्थायी आशुलिपिक-सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर में से, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की स्थायी सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

## 6-आरक्षण-

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

## भाग चार-अर्हताएं

## 7-राष्ट्रीयता-

सेवा में भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो,

या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका (पूर्ववर्ती सीलोन) या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया) (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु अग्रेतर यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

## 8-शैक्षिक अर्हताएं-

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उसकी निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :-

(क) कनिष्ठ सहायक-माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कम्प्यूटर परीक्षा के अन्तर्गत 4000 KDPH (की डिप्रेशन पर आवर) की न्यूनतम गति होनी चाहिये।

(ख) आशुलिपिक-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिये साथ ही कम्प्यूटर पर टंकित करने का ज्ञान होना चाहिये। कम्प्यूटर परीक्षा के अन्तर्गत 4000 KDPH (की डिप्रेशन पर आवर) की न्यूनतम गति होनी चाहिये।

(ग) लेखाकार-सह-कन्सोल ऑपरेटर-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में, जिसमें लेखाशास्त्र एक विषय हो, स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर पर ज्ञान आवश्यक है।

## 9-अधिमानी अर्हताएं-

अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
- (तीन) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्यस्तर अथवा विश्वविद्यालय/कॉलेज स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो, या
- (चार) छंटनीशुदा कर्मचारी हो।

## 10-आयु-

सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जिसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष से अनधिक हो :

परन्तु यह कि लेखाकार-सह-कन्सोल ऑपरेटर के पद के लिये सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।

## 11-चरित्र-

सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : रांघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

## 12-वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

## 13-शारीरिक स्वस्थता-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गये मूल नियम, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

## भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

## 14-रिक्तियों का अवधारण -

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों की पृथक-पृथक भरी जाने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित की जायेगी और उसकी सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को दी जायेगी।

## 15- सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(1) सीधी भर्ती के लिये नियुक्ति प्राधिकारी व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में आवेदन-पत्र का प्रारूप प्रकाशित कर ऐसे पात्र अभ्यर्थियों से, जिन्होंने अपना नाम उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत कराया हो, सीधे आवेदन-पत्र आमंत्रित कर सकेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिये आवेदन-पत्र उप-नियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा।

(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना-पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

(3) किसी भी श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती करने के प्रयोजनार्थ एक चयन-समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन/नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित सहायक विद्युत निरीक्षक- सदस्य

(तीन) उपरोक्त अधिकारियों में से, यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का अधिकारी न हो तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति या जनजाति का अधिकारी- सदस्य

(चार) अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य

(4) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिये 05 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। प्रश्न-पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु  $1/4$  ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र की पुस्तिका (प्रश्न बुकलेट) परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) की, कार्बन प्रति सहित, तीन प्रतियों में होगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की वेबसाइट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) पर प्रदर्शन या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, प्रकाशन किया जायेगा।

(ङ) किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए कम्प्यूटर पर टंकण या आशुलिपि और कम्प्यूटर पर टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, यथास्थिति, कम्प्यूटर पर टंकण या आशुलिपि और कम्प्यूटर पर टंकण की परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा के लिए 4000 KDPH (की डिप्रेशन प्रति घंटा) व आशुलिपि परीक्षा के लिये 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।



(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तार्कों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों तथा यथास्थिति, टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

16-प्रवर सहायक तथा वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल आपरेटर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती-

(1) प्रवर सहायक तथा वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल आपरेटर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- |   |         |
|---|---------|
| (एक) विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी-  | अध्यक्ष |
| (दो) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नामित सहायक विद्युत निरीक्षक-  | सदस्य   |
| (तीन) उपरोक्त अधिकारियों में से, यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का अधिकारी न हो तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति या जनजाति का अधिकारी- | सदस्य   |
| (चार) अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्प संख्यक वर्ग का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी-   | सदस्य   |

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, सुसंगत चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) चयन समिति, चयन किए गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

### भाग छ:-नियुक्ति, परीवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17-नियुक्ति-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम-15 एवं 16 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी कि चयन में अवधारित की जाय।

18-परीवीक्षा-

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अमिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक परीवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परीवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में वह अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।



(4) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसको उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

#### 19-स्थायीकरण-

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-

- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय,
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

#### 20-ज्येष्ठता-

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

#### भाग सात-वेतन इत्यादि

#### 21-वेतनमान-

(1) सेवा के संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नलिखित होंगे :-

क्र०स०	पद का नाम	वेतनमान (रु० में) (छठे वेतनमान के अनुसार)
1.	वैयक्तिक सहायक-सह-कन्सोल ऑपरेटर	5500-175-9000 (9300-34800)
2.	लेखाकार-सह-कन्सोल ऑपरेटर	5000-150-8000 (9300-34800)
3.	प्रवर सहायक	4000-100-6000 (5200-20200)
4.	आशुलिपिक-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	4000-100 6000 (5200-20200)
5.	कनिष्ठ सहायक	3050-75 3950-80-4590 (5200-20200)

#### 22-परिवीक्षा अवधि में वेतन-

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लेने पर और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक कार्य न करने के कारण बढ़ाई जाय तो बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक कार्य न करने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाय तो बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसा व्यक्ति जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

#### भाग आठ-अन्य उपबन्ध

##### 23-पक्ष समर्थन-

किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

##### 24- अन्य विषयों का विनियमन-

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

##### 25-सेवा की शर्तों में शिथिलता-

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, वहां यह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

##### 26-व्यावृत्ति-

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

##### 27-निरसन

इस नियमावली के प्रारम्भ होने की तिथि से यथा संशोधित विद्युत निरीक्षणालय लिपिक वर्गीय नियमावली, 1973 निरसित समझी जायेगी।

आज्ञा से,

शत्रुघ्न सिंह,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 1659/I/2009-01(2)/04/2006, dated October 28, 2009 for general information.

#### NOTIFICATION

October 28, 2009

**No. 1659/I/2009-01(2)/04/2006**--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Electricity Safety Ministerial and Accounts Service :-

#### THE UTTARAKHAND ELECTRICITY SAFETY MINISTERIAL AND ACCOUNTS SERVICE RULES, 2009

##### Part I-General

##### 1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called "The Uttarakhand Electricity Safety Ministerial and Accounts Service Rules, 2009"

(2) They shall come into force at once

## 2. Status of the service--

The Uttarakhand Electricity Safety Ministerial and Accounts Service is a non-Gazetted service comprising Group 'C' posts

## 3 Definitions--

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

- (a) 'Appointing Authority' means Electricity Inspector of Government of Uttarakhand
- (b) 'Electricity Inspector' means Electricity Inspector of Government of Uttarakhand
- (c) 'Electricity Safety Department' means The Electricity Inspector, Government of Uttarakhand Organization,
- (d) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution of India.
- (e) 'Constitution' means the Constitution of India.
- (f) 'Government' means the State Government of Uttarakhand
- (g) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand.
- (h) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service,
- (i) 'Substantive appointment' means an appointment not being an adhoc appointment on a post in the cadre of service made after selection in accordance with the rules and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government, and
- (j) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year

## Part II-Cadre

### 4. Cadre of Service--

(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as follows --

Sl	Designation	No. of Posts		
		Permanent	Temporary	Total
1	Personal Assistant-Cum-Console Operator	1	—	1
2	Accountant-Cum-Console Operator	1	—	1
3	Senior Assistant	1	—	1
4	Stenographer-Cum-Data Entry Operator	3	—	3
5	Junior Assistant	6	—	6

Provided that--(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper

**Part III-Recruitment****5 Source of recruitment :**

Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources namely --

**Designation****(i) Junior Assistant--**

By direct recruitment through competitive examination, by the Appointing Authority

**(ii) Stenographer-Cum-Data Entry Operator--**

By direct recruitment through competitive examination, by the Appointing Authority

**(iii) Senior Assistant--**

By promotion from amongst the permanent Junior Assistants who have completed minimum three years service

**(iv) Accountant-Cum-Console Operator--**

By direct recruitment through competitive examination, by the Appointing Authority

**(v) Personal Assistant-Cum-Console Operator--**

By promotion from amongst the permanent Stenographers-Cum-Data Entry Operators who have completed minimum ten years service

**6. Reservation--**

Reservation for the candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Categories, belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government, in force, at the time of the recruitment.

**Part IV-Qualifications****7. Nationality--**

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be--

- (a) a citizen of India, or
- (b) a Tibetan refugee, who came over to India before 1<sup>st</sup> January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (Formerly Burma), Sri Lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further, that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand

Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship

**Note--** A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his/her favour

**8. Academic Qualifications--**

For direct recruitment to various posts in the Service a candidate must have good knowledge of Hindi written in Devnagari script and must possess the following qualifications --

(a) **Junior Assistant--**Must have passed the Intermediate Examination of the Board of Secondary Education Uttarakhand or any other examination recognized by the Government equivalent thereto. Must have minimum speed of 4000 KDPH (Key Depressions Per Hour) for computer test

(b) **Stenographer-Cum-Data Entry Operator--**Must have passed the Intermediate Examination of the Board of Secondary Education, Uttarakhand or any other examination recognized by the Government equivalent thereto. Must have minimum speed of 4000 KDPH (Key Depressions Per Hour) for computer test and minimum speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and knowledge of typewriting on the computer

(c) **Accountant-Cum-Console Operator--**Graduate in Commerce with Accountancy as one of the subjects from any recognized University or any other Degree recognized by the Government equivalent thereto. Must have knowledge of computers

**9. Preferential Qualifications--**

A candidate shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment who--

- (i) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years or
- (ii) has obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps. or
- (iii) is a sportsman of International/National/State Level or a sportsman of University/College/School level, or
- (iv) who is a retrenched employee

**10. Age--**

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years on July 1st of the calendar year in which the vacancies are advertised for direct recruitment but must not have attained the age of more than 35 years

Provided that prescribed minimum age for the post of Accountant-cum-Console Operator for direct recruitment shall be 21 years

Provided further that in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories as may be notified by the Government from time to time there shall be 05 years relaxation in upper age limit

**11. Character--**

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point

**Note--**Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall not be eligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also not be eligible

**12. Marital status--**

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service

Provided that the Governor may, if he is satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule-

**13. Physical fitness--**

No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he/she shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book Volume I, Part I.I

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion

### Part V-Procedure For Recruitment

#### 14. Determination of Vacancies--

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies for direct recruitment of the post of Junior Assistant and Stenographer-Cum-Data Entry Operator, separately to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories, under Rule 6 and the same shall be intimated to the Employment Exchange in accordance with the rules and orders in force for the time being

#### 15. Procedure for Direct Recruitment--

(1) For direct recruitment Appointing Authority may invite the applications directly from such eligible candidates who have registered themselves with the Employment Exchange of the State of Uttarakhand by publishing the format of the application form in two daily newspapers, having wide circulation

(2) The Appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the format published under sub-rule (1) and notify the vacancies in the following manner --

- (i) by issuing advertisement in such daily news papers, which are having wide circulation
- (ii) by pasting the notice on the Notice Board of the office or by advertisement through Radio/Television and other Employment news papers, and
- (iii) by notifying the vacancies to the Employment Exchanges

(3) For the purpose of direct recruitment to any category of posts, a Selection Committee shall be constituted, comprising the following --

- |       |  |             |
|-------|--|-------------|
| (i)   | Electricity Inspector, Government of Uttarakhand/Appointing Authority  | Chairperson |
| (ii)  | Assistant Electricity Inspector, nominated by the Appointing Authority   | Member      |
| (iii) | An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the District Magistrate, if any of the above officers does not belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes | Member      |
| (iv)  | An officer belonging to Other Backward Classes or Minority Communities shall be nominated by the Appointing authority  | Member      |

- (4) (i) There shall be a written examination carrying 100 marks for the selection. The retrenched employees shall be awarded 5 marks for each year of completed service subject to the maximum of 15 marks. The merit list shall be prepared on the basis of the marks obtained in the written examination and other evaluations

(ii) (a) The written examination shall be objective type consisting of single question paper which will include General Hindi, General Knowledge and General Studies. While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and 1/4 negative mark for each wrong answer

b) After the examination is over, the candidates shall be allowed to carry back the Question Book etc of the written examination with them

c) The Answer-Sheet of the written examination shall be in triplicate (including the carbon copy), and the candidates shall be permitted to carry back the duplicate copy with them

d) After the written examination, the Answer-Key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website [www.uanic.in](http://www.uanic.in) or published in daily newspaper, having wide circulation

(e) In the case of candidates to be selected for a post for which typewriting or shorthand and type writing on the computer is prescribed as an essential qualification, there shall be a typewriting examination or shorthand and typewriting examination on the computer, as the case may be. The minimum prescribed limit for typewriting examination shall be 4000 KDPH (Key Depressions Per Hour) and 80 words per minute for shorthand test. The above examination shall carry 50 marks. Only those candidates shall be awarded marks who have achieved the prescribed minimum speed. The candidates shall be called for the typewriting examination or shorthand and typewriting examination on the basis of the aggregate of the marks obtained by them in the written examination and other



evaluations. The number of candidates to be called for typewriting examination or shorthand and typewriting examination shall be four times the number of vacancies.

(5) The merit list (Final selection list) shall be prepared on the basis of the proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained in the written examination and other evaluations including preferential marks to the retrenched employees and marks of typewriting examination, or shorthand and typewriting examination, as the case may be. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the candidate obtaining more marks in the written examination shall be placed higher in the selection list. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the selection list. The names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies. The Selection list of the candidates shall be valid for a period of one year.

#### **16. Recruitment by promotion to the post of Senior Assistant and Personal Assistant-Cum-Console Operator—**

(1) Recruitment by promotion to the post of Senior Assistant and Personal Assistant-Cum-Console Operator shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, through a Selection Committee comprising the following :—

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| (i)   | Electricity Inspector, Government of Uttarakhand/Appointing Authority   | Chairperson |
| (ii)  | Assistant Electricity Inspector, nominated by the Appointing Authority  | Member      |
| (iii) | An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes nominated by the District Magistrate, if any of the above officers does not belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes | Member      |
| (iv)  | An officer belonging to Other Backward Classes or Minority Communities shall be nominated by the Appointing Authority   | Member      |

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall prepare a list of the selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

#### **Part VI-Appointment, Probation, Confirmation and Seniority**

#### **17. Appointment**

(1) The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 and 16, as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

#### **18. Probation--**

(1) A person on appointment to a permanent post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date upto which the extension is granted.

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he/she may be reverted to his/her substantive post, if any, and if she/he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

**19. Confirmation--**

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--

- (a) his/her work and conduct is reported to be satisfactory,
- (b) his/her integrity is certified, and
- (c) the Appointing Authority is satisfied that he/she is otherwise fit for confirmation.

**20. Seniority--**

The seniority of persons substantively appointed to a post in the Service shall be determined in accordance with the procedure prescribed by the Government from time to time.

**Part VII-Pay Etc.****21. Scales of Pay--**

(1) The Scales of pay, admissible to persons, appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time

(2) The Scales of pay at the time of commencement of these Rules are as follows --

Sl.	Designation	Pay Scale (In Rs.) (According to 6 <sup>th</sup> Pay Scale)
1.	Personal Assistant Grade-II-cum-Console Operator	5500-175-9000 (9300-34800)
2.	Accountant-cum-Console Operator	5000-150-8000 (9300-34800)
3.	Senior Assistant	4000-100-6000 (5200-20200)
4.	Stenographer Grade II-cum-Data Entry Operator	4000-100-6000 (5200-20200)
5.	Junior Assistant	3050-75-3950-80-4590 (5200-20200)

**22. Pay During Probation--**

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by this relevant fundamental rule.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service, shall be regulated by the relevant rules, applicable to the Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

**Part VIII-Other Provisions****23. Canvassing--**

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly, for his candidature will disqualify him/her for appointment.

**24. Regulation of other matters--**

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

**25. Relaxation from the conditions of service--**

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the Service, cause undue hardship in any particular case, if may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner

**26. Saving--**

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

**27. Repeal-**

The Electricity Inspectorate Ministerial Rules, 1973, as amended from time to time, shall stand repealed with effect from the date of commencement of these Rules.

By Order,

SHATRUGHNA SINGH,  
Secretary.

**परिवहन अनुभाग-1****अधिसूचना**

12 नवम्बर, 2009 ई०

संख्या 316/IX/216/2009-10- मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, रान् 88) की धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अनुमोदित योजना में नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक, प्रत्येक के समक्ष उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिसूचित मार्गों के सम्बन्ध में, लोकहित में उपान्तर करने का प्रस्ताव करते हैं और उसे उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम और प्रस्तावित उपान्तरों द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त यात्रियों की सूचना के लिये और उसे अभ्यावेदन यदि कोई हो, आमन्त्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करते हैं।

2- उत्तराखण्ड परिवहन निगम और अन्य कोई व्यक्ति, जिसका हित प्रस्तावित उपान्तर द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, अभ्यावेदन, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को कर सकता है।

3- इस प्रकार इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई, सुनवाई प्राधिकारी श्री विनोद शर्मा, अपर सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्रातः 10.00 बजे उनके उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में की जायेगी।

**अनुसूची**

क्र०सं०	अधिसूचित मार्ग का नाम जिसका उपान्तर प्रस्तावित है	प्रस्तावित उपान्तर
1.	बहादुराबाद-पिरानकलियर-रोशनाबाद-रुडकी	निजी क्षेत्र की मिनी बसों के संचालन हेतु

आज्ञा से,

उमाकान्त पंवार,  
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 47 हिन्दी गजट/548-भाग 1-2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक २१ नवम्बर, २००९ ई० (कार्तिक ३०, १९३१ शक सम्बत)

भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, दिशानिर्देश इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 28, 2009

No. 199/UHC/XIV-90/Admin.A--Sri Mithilesh Jha, Civil Judge (Jr Div ), Bageshwar, is hereby sanctioned earned leave for 07 days w.e.f. 03.10.2009 to 09.10.2009 with permission to prefix 02.10.2009 as Gandhi Jayanti and to suffix 10.10.2009 and 11.10.2009 as 2<sup>nd</sup> Saturday & Sunday holidays

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,  
Registrar (Inspection),

October 30, 2009

No. 200/UHC/Admin.A/2009--Sri Servesh Kumar Gupta, Chairman, Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand, Dehradun (additional Charge of Legal Advisor to H. E. the Governor of Uttarakhand) is repatriated and posted as District & Sessions Judge Hardwar vice Sri P.K. Agarwal on his superannuation on 31.10.2009.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

RAVINDRA MAITHANI,  
Registrar General

पी०एस०यू० (आ०ई०) ४७ हिन्दी गजट/५४८ भाग १ क २००९ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।